फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 115 प्रभात जयपुर, गुरूवार 26 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com



Not a word spoken

Sometimes, the communication is in the wrinkled forehead. At other times, it is in the eyes. Most dangerously, it is in the silence

The Secret Behind the Blue

Qing dynasty jewellery often combined these vivid blue feathers with gold, pearls, coral, glass and semi-precious stones

आज बुधवार को राहुल गांधी अमेरिका से लौटे

कल, गुरुवार से, ''गुरु'' के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शनों का सिलसिला शुरु

- कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों का फोकस है, ''वोट चोरी'' तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्ती। जब तक इन मुद्दों का निराकरण नहीं होता, संसद को चलने नहीं दिया जाएगा।
- अभी तक संसद के मानसून सत्र का अवसान नहीं किया गया है। अतः तुरंत आनन-फानन में मानसून सत्र के अवसान की कार्यवाही शुरु की जा सकती है।
- अभी स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस मुतल्लिक क्या करना चाहती है, क्योंकि अभी सरकार के पास सांसदों की पर्याप्त संख्या नहीं है, संविधान में संशोधन का विधेयक पारित करा सके। पार्टी किसी भी तरह अपने संविधान संशोधन विधेयक को सदन में गिरने नहीं देना चाहती।
- बहरहाल, राहुल गांधी अपना विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चलाना चाहते हैं, जिससे ''मैसेज'' जाए कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार की बर्खास्ती व ''एस.आई.आर.'' के मुद्दे पर, पूरी तरह गंभीर है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। अमेरिका के दौरे के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं, और कल से कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है।

पार्टी, संसद का सत्र नहीं बुलाए जाने, संविधान से जुड़े मुद्दे और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुद्दा भी शामिल है।

पार्टी राहुल गांधी के लौटने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब वे विरोध प्रदर्शनों के ''गुरु'' बन गए हैं। वे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और नई ऊर्जा भरते हैं और उन्हें सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने तथा उसे घेरने के लिए प्रेरित करते हैं।

फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि संसद का सत्र कब बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी तक इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है।

वहीं, मानसून सत्र को आगे जारी रखने के लिए तत्काल बैठक बुलाई जा सकती है।

सरकार की ओर से कई तरह की बातें और जानकारियां सामने रखी जा रही हैं, लेकिन चूँकि उनके पास संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है और सरकार यह जोखिम भी नहीं उठा सकती कि विधेयक सदन में गिर जाए, इसलिए फिलहाल स्थिति पूरी तरह अनिश्चित बनी हुई है। मानसून सत्र को अभी तक अधिकारिक तौर पर समाप्त नहीं किया गया है। ऐसे में यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि सरकार आखिर क्या चाहती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो बनीं मिस यूनिवर्स



नई दिल्ली, 25नवंबर। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 75वां संस्करण संपन्न हो गया है, जिसमें पोर्तो रिको की जेनिफर बैरेटो विजेता बनीं। मौजूदा मिस यूनिवर्स, मेक्सिको की फातिमा बॉश ने अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाया।

जेनिफर यह खिताब जीतने वाली पहली शादीशुदा महिला और मां हैं। उन्होंने फरवरी 2026 में पहली बार रैंप वॉक किया था। जून में मिस यूनिवर्स पोर्तो रिको का खिताब जीतने के बाद वे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहुंचीं। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए 30 किलो वजन भी घटाया। जेनिफर ने भारतीय कारीगरों की बारीक कढ ाई से सजा एक खास गाउन पहना था।

उनकी जीत के साथ पोर्तो रिको ने छठी बार यह ताज जीता हैं।

इस प्रतियोगिता में डोमिनिकन रिपब्लिक की मेलिसा नुनेज फर्स्ट और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'विधानसभा चुनाव में, भाजपा का चेहरा कमल होगा, न कि योगी आदित्यनाथ'

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जौनपुर में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात उजागर की

- एबीपी के कॉन्क्लेव में, हालांकि, केशव प्रसाद मौर्य ने लीपापोती करने की कोशिश की।
- इस कॉन्क्लेव में, जब योगी आदित्यनाथ से चुनाव के बाद मु.मंत्री के पद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेफिक्री से कहा, ''सब जानते हैं, कौन मु.मंत्री है और कौन मु.मंत्री बनेगा।''

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 नवंबर। अगर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को गंभीरता से लिया जाए तो इस सबसे बड़े राज्य में भगवा पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मौर्य ने आज कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा का चुनाव चिन्ह 'कमल' ही पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। उनके इस बयान से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेमे में हलचल मच गई है।

मौर्य ने कभी भी मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा छिपाई नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जीते हुए विधायक और पार्टी के केन्द्रीय पर्यवेक्षक तय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या किसी और को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।

बताया जाता है कि मौर्य केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं और उनके निर्देशानुसार काम करते हैं। यह भी विदित ही है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते।

जौनपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मौर्य ने कहा, ''चुनाव के दौरान भाजपा का चेहरा उसका चुनाव चिह्न 'कमल' होता है। चुनाव खत्म होने और विधायकों के चुने जाने के बाद, उनकी बैठक होती है। केन्द्रीय पर्यवेक्षक आते हैं और उस बैठक में बनी सहमति के आधार पर नेता चुना जाता है। फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वे आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कोई और यह जिम्मेदारी संभालेगा, यह फैसला करना मेरे हाथ में नहीं है। इसका फैसला उस समय चुने गए विधायक करेंगे।''

मौर्य का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी उनके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेदों की खबरें आती रही हैं।

हालांकि इससे पहले, एबीपी न्यूज के एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया था।

उन्होंने कहा था कि भाजपा एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुरुवार को लखनऊ में विशाल धरने, प्रदर्शन व मार्च किए जा रहे हैं

मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा के अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी व चंद्रशेखर, अपने-अपने नवगठित गठबंधनों की राजनीतिक रैलियां आयोजित कर रहे हैं

- हालांकि, कई मार्च व प्रदर्शनों को अभी सरकार की ओर से आयोजित करने की स्वीकृति नहीं मिली है। पर, लगभग सभी राजनीतिक दल व गठबंधन अनुमति न मिलने को मुद्दा नहीं बना रहे हैं, बल्कि मार्च के लिए वैकल्पिक रुख अपना रहे हैं।

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 नवंबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की अहम राजनीतिक लड़ाई का माहौल तैयार करते हुए, गुरुवार को लखनऊ में राजनीतिक कार्यक्रमों की हलचल रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य सरकार द्वारा पैदल मार्च की अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद, लखनऊ में पार्टी के 'संविधान रक्षा सम्मेलन' में शामिल होंगे। इसी दिन समाजवादी पार्टी अपना 'पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक' घोषणापत्र जारी करेगी। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी का नया गठबंधन भी राजधानी में अपनी पहली संयुक्त राजनीतिक रैली करेगा।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने संविधान रक्षा सम्मेलन के तहत पैदल मार्च निकालने की योजना बनाई थी। इसकी शुरुआत गांधी भवन में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होनी थी और समापन हजरतगंज में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर होना था। लेकिन अधिकारियों द्वारा मार्च की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कार्यक्रम को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित करने का फैसला किया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डीजे बंद कराने गई पुलिस टीम पर हमला

जयपुर, 25 नवंबर । खो नागोरियान थाना इलाके में डीजे बंद करवाने पहुंची पुलिस टीम के साथ मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने

- खो नागोरियान में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार।

का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब एक दर्जन लोगों ने उपनिरीक्षक (एसआई) रामफूल सहित, पुलिसकर्मियों के साथ लात-घूंसों और थप्पड़ों से मारपीट की। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी और उनके मोबाइल फोन छीनकर जमीन पर पटककर तोड़ दिए।

घटना 23 नवंबर की देर रात करीब 12 बजे की है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, एसआई रामफूल पुलिस जाप्ते के साथ इलाके में डीजे बंद करवाने पहुंचे थे। वहां मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से चुनावी गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है

पंजाब में अकाली दल व भाजपा के गठबंधन के बाद, ष पंजाब में राजनीतिक गठबंधनों का फैशन चल पड़ा है

- प्रदेशाध्यक्ष परगट सिंह व विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गठबंधन की संभावनाओं का स्वागत किया।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। पंजाब के विधानसभा चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल (एस.ए.डी.) और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन पक्का हो जाने के बाद, अब कांग्रेस वामपंथी दलों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के साथ चुनावी गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है। इससे राज्य में राजनीतिक गठबंधन के नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने पुष्टि की है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और इस संबंध में कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी गठबंधन की संभावना का समर्थन किया है, जिससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस के राज्य नेतृत्व में इस प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त है।

हालांकि कांग्रेस ने बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन प्रस्तावित गठबंधन का स्वरूप, खासकर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। परगट सिंह और बाजवा ने संकेत दिया है कि सीटों का बंटवारा सभी पार्टियों की भूमिका और उनकी राजनीतिक ताकत को ध्यान में रखकर किया जाएगा। फिलहाल, अलग-अलग सीटों पर बातचीत शुरू करने से पहले एक आपसी सहमति बनाने की संभावना तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।

बदले हुए राजनीतिक माहौल में यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के दोबारा साथ आने से राज्य के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। दोनों पूर्व सहयोगी कई वर्षों तक अलग रहने के बाद फिर एक साथ आए हैं, जिससे उनके संगठनात्मक नेटवर्क और समर्थक आधार एक साझा चुनावी ढांचे में आ गए हैं। उनके गठबंधन के बाद अन्य राजनीतिक दलों ने भी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करना शुरू कर दिया है।

सीजेपी के सौरभ दास से जन्मस्थान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा

नई दिल्ली, 25 नवंबर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास के पासपोर्ट में दी गई जन्मस्थान की जानकारी को लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने प्रश्न खड़ा किया था जिसके बाद उनसे

- उल्लेखनीय है कि उन्हें लंदन जाते समय एयरपोर्ट पर रोका गया था।

स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनसे कहा गया है कि स्पष्टीकरण मिलने तक वे अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल न करें।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में एक प्रश्न पर कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपेक्षा की जाती है कि आवेदक सही जानकारी दें। इसमें कमी या त्रुटि पाए जाने पर आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। चेन्नई के क्षेत्रीय कार्यालय से आधिकारिक जानकारी मिलने पर नोटिस दिया गया है। सौरभ दास को सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है और जवाब मिलने तक पासपोर्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में दस में से नौ महिलाएं, मैट्रो स्टेशन या बस स्टॉप के रास्ते में भारी असुरक्षा महसूस करती हैं

एक समाचार एजेंसी द्वारा प्रसारित सर्वे रिपोर्ट में यह चिंताजनक ष पहलू पूर्णतया उजागर हुआ

- इस असुरक्षा की जड़ में है, दिल्ली शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तथा पुरुषों का आपत्तिजनक व्यवहार।
- महिलाओं ने यह भी कहा, सर्वे के दौरान, कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि किसी सरकारी एजेंसी से कैसे संपर्क किया जाए व शिकायत की जाए तथा किस सरकारी एजेंसी की जिम्मेवारी है, सड़कों और रास्तों को महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने की।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 नवंबर। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में सर्वेक्षण में शामिल करीब 10 में से 9 महिलाओं और लड़कियों का कहना है कि निकटतम मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप तक जाते समय वे खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं।

सेंटर फॉर इक्विटी एंड इन्क्लूजन (सीक्विन) के इस अध्ययन में पाया गया कि खराब बुनियादी सुविधाएं, पुरुषों का अनुचित व्यवहार और सार्वजनिक स्थानों की देख-रेख के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेवार है, इसे लेकर अनिश्चितता लोगों की शहर में स्वतंत्र रूप से आने-जाने की क्षमता को प्रभावित करती है।

सीक्विन के एक बयान के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 87.5 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे निकटतम मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप तक पैदल जाते समय असुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि 88.9 प्रतिशत ने अंधेरा होने के बाद अपने निकटतम सार्वजनिक पार्क में असुरक्षित महसूस करने की बात कही। तीन-चौथाई से अधिक महिलाओं ने बताया कि फुटपाथों पर पर्याप्त रोशनी नहीं होती। वहीं, 60 प्रतिशत ने कहा कि फुटपाथ टूटे हुए हैं या कई जगह मौजूद ही नहीं हैं।

ये निष्कर्ष 1,588 महिलाओं, लड़कियों और एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं। सीक्विन ने कहा कि सुरक्षा को लेकर चिंताएं केवल यौन हिंसा के खतरे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें वे परिस्थितियां भी शामिल हैं, जिनका सामना लोगों को रोजाना शहर में आते-जाते समय करना पड़ता है।

करीब 80 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि पुरुषों का व्यवहार, जिसमें घूरना, अश्लील टिप्पणियां करना और पीछा करना शामिल है, उनकी रोजमर्रा की यात्राओं को असुरक्षित बनाता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि 80.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को यह जानकारी नहीं थी कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कौन-सी नागरिक एजेंसी जिम्मेदार है। इस कारण उन्हें यह समझ नहीं आता कि सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा होने पर वे किससे संपर्क करें।

''एवरीडे जर्नीज: विमेन्स एंड गर्ल्स एक्सेस टू फुटपाथ एंड पब्लिक पार्क्स इन दिल्ली'' नामक इस अध्ययन में बताया गया है कि किस तरह बुनियादी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को जमानत मिली

जयपुर, 25 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन

- एसीबी ने जल जीवन मिशन घोटाले में उन्हें 9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया था।

घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित, विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता दिनेश दिनेश गोयल व अधीक्षण अभियंता महेन्द्र प्रकाश सोनी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि अपीलार्थियों के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन हजारों पेज के विस्तृत रिकॉर्ड व 124 गवाहों के दर्ज होने वाले प्रस्तावित बयानों को देखते हुए लगता है कि ट्रायल में लंबा समय लगेगा। अभी तक आरोप भी तय नहीं हो पाए हैं। अन्य सह आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित, अन्य आरोपियों को भी इस अदालत व हाईकोर्ट ने जेल से बाहर आने की मंजूरी दे दी है। इसलिए आरोपियों को हिरासत में रखना किसी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। इसलिए तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करना उचित होगा। जस्टिस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)